

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रमान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 15/2019  
आरसीएमएस नम्बर : 2019/00031

प्रार्थी :-  
मूलचन्द पुत्र सरमल नाहर, जाति  
जैन, निवासी मारवाड जंक्शन जिला  
पाली (राज.)

बनाम  
अप्रार्थी :-  
ग्राम पंचायत जाणुन्दा मार्फत सरपंच  
ग्राम जाणुन्दा तहसील मारवाड जंक्शन  
जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति -

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन चौहान  
अप्रार्थी अनुपस्थित

-: निर्णय :-

दिनांक :- 15.02.2021

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कायम मिसल संख्या 244 दिनांक 03.03.2013 एवं प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 69 दिनांक 05.07.2014 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने स्वामित्वसुदा व कब्जासुदा भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत जाणुन्दा के समक्ष आवेदन पेश किया। जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 244 दिनांक 03.03.2013 को कायम की गई, लेकिन मिसल की किसी भी ओदशिका पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर हैं, न ही ग्राम सेवक के हस्ताक्षर हैं। पट्टा जारी करने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना किए बिना ही जारी किए गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। नियम 148 के तहत आक्षेप आमन्त्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया, उस पर दिनांक का अंकन नहीं है तथा न ही किसी जिम्मेदार के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त मिसल का औचित्य ही नहीं रह जाता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने कब्जासुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का आवेदन करने पर ग्राम पंचायत पंचायती राज नियमों की पालना नहीं कर आनन-फानन में नियम विरुद्ध पट्टा जारी कर दिया। जिस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे का न तो नवीनीकरण करवाया जा सकता है, न ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है तथा न ही उक्त पट्टे का वह कानूनी रूप से कहीं उपयोग कर सकता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में जारी विक्रय विलेख एवं प्रस्ताव को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया है तथा प्रार्थी स्वयं अपने नाम जारी विक्रय विलेख को निरस्त करवाना चाहता है। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो विक्रय विलेख जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायत



*(Signature)*

राज नियम 1996 के नियमों की पालना में जारी किया है या नहीं। मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी जिस भूखण्ड का पट्टा जारी करवाना चाहता है, उसके संबंध में किया गया आवेदन मिसल के संलग्न नहीं है, जबकि बिना आवेदन पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 244 दिनांक 03.03.2013 को कायम की है, लेकिन उक्त मिसल की किसी भी ओदशिका पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर हैं तथा न ही ग्राम सेवक के हस्ताक्षर हैं, आक्षेप आमन्त्रित करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया है, उस पर न तो दिनांक का अंकन है, न ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, न ही ग्राम पंचायत की मोहर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि जो मिसल कायम की गई है, उसका विधिक रूप से कोई आधार नहीं है तथा जो पट्टा जारी किया गया है, वह प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 की पालना में जारी किया गया है, जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 05.07.2013 के प्रस्ताव संख्या 3 में मिसल संख्या 244 उल्लेख नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पक्ष में जो विक्रय विलेख जारी किया है, वह पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विरुद्ध जाते हुए जारी किया है, जिसे यथावत रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में मिसल संख्या 244 दिनांक 03.03.2013 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.07.2013 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 05.07.2014 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत जाणुन्दा को भिजवाया जावे।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)  
जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)  
जिला कलेक्टर, पाली